



# भारत का राजपत्र

# The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 102]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 28, 2019/चैत्र 7, 1941

No. 102]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 28, 2019/CHAITRA 7, 1941

## वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

## जांच की शुरुआत की अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2019

(मामला संख्या ओ. आई. 03/2019)

**विषय:** कोरिया गणराज्य और चीन जनवादी गणराज्य से "क्लोरीनेटेड पॉलीविनाइल क्लोराइड (सीपीवीसी) – आगे सम्मिश्रण में प्रसंस्कृत हो अथवा नहीं" के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरुआत।

1. फा. सं. 06/03/2019-डीजीटीआर.—मैसर्स डीसीडब्ल्यू लिमिटेड और मैसर्स केम वन केमप्लास्ट प्रा. लि. (जिन्हें यहां आगे "याचिकाकर्ता" अथवा "आवेदक" कहा गया है) ने समय-समय पर यथा संशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे वाद में अधिनियम कहा गया है) और उसकी समय-समय पर यथा संशोधित सीमा प्रशुल्क (पाटित आयातों पर पाटनरोधी शुल्क की जांच, मूल्यांकन एवं संग्रहण तथा क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 (जिसे आगे यहां नियमावली भी कहा गया है) के अनुसार चीन जन. गण. और कोरिया गणराज्य (जिन्हें आगे संबद्ध देश कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित क्लोरीनेटेड पॉलीविनाइल क्लोराइड (जिसे यहां आगे संबद्ध सामान अथवा विचाराधीन उत्पाद कहा गया है) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरुआत के लिए निर्दिष्ट प्राथिकारी (जिसे यहां आगे प्राथिकारी कहा गया है) के समक्ष आवेदन दायर किया।

## क. विचाराधीन उत्पाद

2. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद "क्लोरीनेटेड पॉलीविनाइल क्लोराइड (सीपीवीसी) – आगे सम्मिश्रण में प्रसंस्कृत हो अथवा नहीं" है। सीपीवीसी रेसिन सीपीवीसी सम्मिश्रण बनाने के लिए स्टेबलाइजर, लुब्रिकेंट, इम्पैक्ट बॉडीफायर्स, प्रोसेसिंग एड्स, पिगमेंट्स जैसे घटकों के साथ प्रसंस्कृत किया जाता है। सीपीवीसी दो ग्रेडों - (क) पाइप ग्रेड तथा (ख) फिटिंग ग्रेड में उपलब्ध है।

3. सीपीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड रेसिन के क्लोरीनेसिन से उत्पादित थर्मोप्लास्टिक है। यह काफी अधिक लचीला होता है और मानक पीवीसी की अपेक्षा अधिक तापमान को सहन कर सकता है। सीपीवीसी में उच्चत तापमानों पर उत्कृष्ट क्षरण प्रतिरोधकता होती है। सीपीवीसी आदर्श रूप से स्व-समर्थक निर्माणों के लिए उपयुक्त होता है जहां तापमान 200 डिग्री फारेनहाइड (90 डिग्री सेल्सियस) तक विद्यमान होता है। सीपीवीसी काफी डकटाइल होता है जो अधिक लचीलापन और अपवर्धण प्रतिरोधकता होने देता है। अतिरिक्त रूप से, सीपीवीसी की यांत्रिक शक्ति उसे उन स्थितियों में धात्विक पाइप की कई किस्मों को बदलने के लिए अर्थक्षम घटक बना देता है जहां धातु की क्षरण के लिए संवेदनशीलता उसके प्रयोग को सीमित करती है। यह विशिष्ट रूप से जलाने के लिए बहुत कठिन है और तब अपने आप ही इसके बुझने की प्रवृत्ति होती है जब सीधे ही ज्वाला न लगाई जाए।
4. विचाराधीन उत्पाद सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 के अध्याय 39 और उप शीर्ष 39049000 के अंतर्गत वर्गीकृत है। तथापि, इस उत्पाद को इन उप-शीर्षों 39042110, 39042190, 39042210, 39042290 और 39049000 के तहत भी आयातित किया गया है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और जांच के क्षेत्र पर वाध्यकारी नहीं है।

#### **ख. समान वस्तु**

5. आवेदक ने दावा किया है कि यद्यपि संबद्ध सामानों का उत्पादन दो प्रक्रियाओं (शुष्क प्रक्रिया और आर्द्र प्रक्रिया) के माध्यम से किया जाता है। तथापि, प्रयोग की जा रही भिन्न प्रौद्योगिकी के कारण उत्पाद में कोई अंतर नहीं है। आवेदक ने यह भी दावा किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित विचाराधीन उत्पाद भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं, प्रकार्य एवं प्रयोग, उत्पाद विशिष्टियों, कीमत, वितरण एवं विपणन तथा संबद्ध देश से आयातित संबद्ध सामानों के प्रशुल्क वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय है।
6. आवेदक ने यह भी दावा किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध सामान संबद्ध देशों से आयातित उन सामानों में तकनीकी रूप से और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय है और इसीलिए नियमावली के तहत उसे "समान वस्तु" माना जाना चाहिए। अतः वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए प्राधिकारी भारत में घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध सामानों को संबद्ध देशों से आयात किए जा रहे विचाराधीन उत्पाद की "समान वस्तु" मानते हैं।

#### **ग. घरेलू उद्योग और आधार**

7. यह याचिका मैसर्स डीसीडब्ल्यू लिमिटेड द्वारा दायर की गई है। मैसर्स केम वन केमप्लास्ट प्रा. लि. ने भी पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की मांग करते हुए अलग से याचिका की है। मैसर्स डीसीडब्ल्यू ने दावा किया है कि वह वर्तमान में भारत में संबद्ध सामानों का एकमात्र उत्पादक है तथा बाजार में एक नया प्रवेशक है। मैसर्स केम वन केमप्लास्ट प्रा. लि. ने दावा किया है कि उसका इस उत्पाद के उत्पादन के लिए विनिर्माण सुविधाएं स्थापित करने का इरादा है और देश में इस उत्पाद के पाठन के कारण प्रतिकूल बाजार के महेनजर अपने निवेश को रोककर रखा था। उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार आवेदक कंपनी अर्थात् मैसर्स डीसीडब्ल्यू पूरा घरेलू उत्पादक है और नियम 2(ख) के अभिप्राय से घरेलू उद्योग बनने के लिए पात्र है तथा उपर्युक्त नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार आधार के मानदंडों को पूरा करता है। मैसर्स केम वन केमप्लास्ट प्रा. लि. को भी तथापि परियोजना चरण पर संबद्ध सामानों का भारतीय उत्पादक माना जाता है तथा जांच प्रक्रिया के दौरान उसकी जांच की जाएगी।
8. भारत में ऐसी कुछ कंपनियां हैं जो सीपीवीसी रेसिन का उत्पादन नहीं करतीं बल्कि सीपीवीसी रेसिन का आयात करती हैं, उसे सम्मिश्रण में प्रसंस्कृत करती हैं जो कि व्यापक रूप से पाइप बनाने के लिए कैप्टिव खपत के लिए किया जाता है। तथापि, एक ऐसी कंपनी भी है जो अपने संबद्ध आपूर्तिकर्ता से रेसिन का आयात कर रही है, उसे सम्मिश्रण में प्रसंस्कृत कर रही है और बाजार में वेच रही है। याचिकार्ता ने यह भी उल्लेख किया है कि चीन और कोरिया से रेसिन के कुछ आयातक हो सकते हैं जो अपनी कैप्टिव खपत के अलावा बाजार में सम्मिश्रण की बिक्री कर रहे हों। जिन कंपनियों के पास सीपीवीसी रेसिन के उत्पादन के लिए विनिर्माण सुविधाएं नहीं हैं और सम्मिश्रण में आयातित रेसिन का प्रसंस्करण करने के लिए केवल सम्मिश्रणकर्ता हैं, उन्हें नियम 2(ख) के अनुसार प्रस्तावित जांच के प्रयोजन के लिए इस उत्पाद का "घरेलू उत्पादक" नहीं माना गया है।

#### **घ. संबद्ध देश**

9. वर्तमान जांच चीन जन. गण. और कोरिया गणराज्य से विचाराधीन उत्पाद के तथाकथित पाठन के संबंध में है।

### **ड. सामान्य मूल्य**

10. याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि चीन जन. गण. को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना जाना चाहिए और सामान्य मूल्य का निर्धारण नियमावली के अनुबंध-I, नियम 7 के अनुसार किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता ने तीसरे देशों अर्थात् जापान, थाइलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका से भारत में आयात कीमतों के आधार पर चीन में सामान्य मूल्य का दावा किया है क्योंकि याचिकाकर्ता बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत अथवा निर्मित मूल्य के संबंध में संगत सूचना प्राप्त नहीं कर पाया। तथापि, प्राधिकारी ने प्रथम दृष्टया नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 के अनुसार परिकलित निर्मित मूल्य के आधार पर संबद्ध देशों में संबद्ध सामानों के सामान्य मूल्य पर विचार किया है।
11. याचिकाकर्ता ने उन कीमतों के आधार पर कोरिया गणराज्य के लिए सामान्य मूल्य का दावा किया है जिन पर कोरिया में घरेलू उपभोक्ता अंतर्राष्ट्रीय आपूर्तिकर्ताओं से घरेलू खपत के लिए सामग्री की खरीद कर रहे हैं। याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि कोरिया गणराज्य में यह खपत कीमत समान वस्तु के लिए दी गई व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में तुलनीय कीमत है और इसीलिए धारा 9क1(ग) के तहत निर्धारित "खपत कीमत" परीक्षण को पूरा करती है। प्राधिकारी ने प्रथम दृष्टया इस जांच की शुरूआत के प्रयोजन के लिए आवेदकों द्वारा उपलब्ध कराए गए निर्मित मूल्यों के आधार पर संबद्ध देशों में संबद्ध सामानों के सामान्य मूल्य पर विचार किया।

### **च. निर्यात कीमत**

12. निर्यात कीमत याचिकाकर्ता द्वारा डीजीसीआईएंडएस के आयात आंकड़ों के आधार पर और समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, बैंक प्रभार, पत्तन व्यय और सार-संभाल प्रभार आदि के निर्मित समायोजन करने के बाद आंकलित की गई है। जांच प्रक्रिया के दौरान प्राधिकारी वाणिज्यिक आसूचना एवं सांछियकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस) से लेन-देन वार आयात आंकड़ों का विश्लेषण भी करेंगे।

### **छ. पाटन मार्जिन**

13. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना कारखानागत स्तर पर की गई है जो संबद्ध देशों से काफी पाटन मार्जिन दर्शाती है। इस बात के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं कि संबद्ध देशों में संबद्ध सामानों के सामान्य मूल्य कारखानागत निर्यात कीमत से काफी अधिक हैं जो प्रथम दृष्टया यह दर्शते हैं कि संबद्ध देशों से निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में संबद्ध सामानों का पाटन किया जा रहा है।
14. पाटनरोधी जांच की शुरूआत का औचित्य बनाने के लिए काफी पाटन मार्जिन के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं।

### **ज. क्षति एवं कारणात्मक संपर्क**

15. घरेलू उद्योग को क्षति के मूल्यांकन के लिए आवेदक द्वारा दी गई सूचना पर विचार किया गया है। आवेदक ने पूर्ण दृष्टि से और उत्पादन एवं खपत, कीमत न्यूनीकरण, कम कीमत पर बिक्री, काफी वित्तीय हानियों, नियोजित पूंजी पर नकारात्मक आय, विभिन्न मानदंडों के रूप में नकारात्मक वृद्धि आदि के संबंध में पाटित आयातों की बढ़ी हुई मात्रा के रूप में तथाकथित पाटन के परिणामस्वरूप हुई क्षति के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं।
16. आवेदक ने यह भी दावा किया है कि विचाराधीन उत्पाद का पाटन वास्तविक रूप से घरेलू उद्योग की स्थापना की मंदी कर रहा है। घरेलू उद्योग का उत्पादन, बिक्री, क्षमता उपयोग और बाजार हिस्सा देश में उत्पाद के लिए मांग पर विचार करते हुए और यह मानते हुए कि घरेलू उद्योग ने कुछ ही समय पूर्व वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया, काफी कम है।
17. उपर्युक्त से प्राधिकारी संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों के पाटन, घरेलू उद्योग को क्षति तथा तथाकथित पाटन और मौजूदा क्षति के बीच कारणात्मक संपर्क का पर्याप्त साक्ष्य पाते हैं जो तथाकथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव को निर्धारित करने और पाटनरोधी शुल्क की मात्रा की सिफारिश करने (जो यदि लगाई जाए), सिद्ध करने के लिए तथा घरेलू उद्योग को "क्षति" समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, निर्धारित करने के लिए नियमावली के नियम 5 के अनुसार पाटनरोधी जांच की शुरूआत का औचित्य बनाते हैं।

### **झ. पाटनरोधी जांच की शुरूआत**

18. निर्दिष्ट प्राधिकारी उपर्युक्त पैराग्राफों के मद्देनजर संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों के तथाकथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव के संबंध में पाटनरोधी जांचे शुरू करते हैं।

**अ. जांच की अवधि**

19. वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए जांच की अवधि 01 अप्रैल, 2017 से 30 सितंबर, 2018 (18 माह) है। तथापि, अति जांच अवधि में 2014-15, 2015-16, 2016-17 की अवधियां और जांच की अवधि शामिल होंगी। जांच की अवधि को घरेलू उद्योग के आंकड़ों की छोटी लंबाई के मद्देनजर क्षति विश्लेषण के प्रयोजन के लिए तिमाहियों में बांटा गया है। जांच की अवधि के बाद के आंकड़ों की भी घरेलू उद्योग के निष्पादन का विश्लेषण करने के लिए जांच की जा सकती है।

**ट. समय-सीमा**

20. वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी सूचना लिखित में भेजी जानी चाहिए ताकि वह प्राधिकारी को इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से किसी भी हालत में 40 दिन से अनधिक तक उपर्युक्त पते पर प्राप्त हो जाए। यदि निर्धारित समय-सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अपूर्ण है तो प्राधिकारी पाठनरोधी नियमावली के अनुसार रिकार्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम रिकार्ड कर सकते हैं।

21. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे वर्तमान मामले में अपने हित (हितों की प्रकृति सहित) सूचित करें और अपने प्रश्नावली के उत्तर दायर करें तथा इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस दिन (40 दिन) के भीतर घरेलू उद्योग के आवेदन पत्र पर अपनी टिप्पणियां दें। यह सूचना हार्ड कॉफी तथा सॉफ्ट कॉफी में प्रस्तुत की जानी चाहिए।

**ठ. सूचना प्रस्तुत करना**

22. संबद्ध देशों के ज्ञात नियांतिकों, भारत में उनके दूतावास के माध्यम से संबद्ध देश की सरकार, उत्पाद से संबंधित ज्ञात भारत में आयातकों और प्रयोक्ताओं को निर्धारित स्वरूप और तरीके में संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए तथा निम्नलिखित पते पर प्राधिकारी को अपने ज्ञात विचार देने के लिए अलग से संबोधित किया जा रहा है:

**महानिदेशक****व्यापार उपचार महानिदेशालय****वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय****वाणिज्य विभाग****(व्यापार उपचार महानिदेशालय)****चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग,****5 संसद मार्ग, नई दिल्ली 110001**

23. कोई भी अन्य हितबद्ध पक्षकार निर्धारित स्वरूप और तरीके ([www.dgtr.gov.in](http://www.dgtr.gov.in) पर प्राधिकारी की वेबसाइट से डाउनलोड किए जाने योग्य) में ऊपर निर्धारित समय-सीमा के भीतर इस जांच से संगत अपने अनुरोध कर सकते हैं। प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले पक्षकार से यह अपेक्षित है कि वे उसका अगोपनीय रूपांतर प्रस्तुत करें जो अन्य पक्षकारों को उपलब्ध कराया जाएगा।

**ड. अगोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना**

24. यदि प्रश्नावली के उत्तर/अनुरोधों के किसी भाग के संबंध में गोपनीयता का दावा किया गया है तो वह दो अलग-अलग सेटों में प्रस्तुत किया जाना चाहिए (क) गोपनीय चिन्हित (शीर्षक, सूची, प्रश्नों की संख्या आदि) और (ख) दूसरा सेट अगोपनीय के रूप में चिन्हित (शीर्षक, सूची, प्रश्नों की संख्या आदि)। दी गई पूरी सूचना पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर "गोपनीय" अथवा "अगोपनीय" लिखा होना चाहिए। हितबद्ध पक्षकारों से अपेक्षा है कि वे इस निदेशालय की 07 सितंबर, 2018 की व्यापार सूचना संख्या 10/2018 में निहित दिशा-निर्देशों का पालन करें।

25. कोई भी दी गई सूचना, जिस पर गोपनीय नहीं लिखा होगा, को अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी को उस अगोपनीय सूचना का निरीक्षण करने के लिए अन्य हितबद्ध पक्षकारों को अनुमति देने की स्वतंत्रता होगी। गोपनीय रूपांतर और अगोपनीय रूपांतर की दो (02) प्रक्रियाएं सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत की जानी चाहिए।

26. गोपनीय के रूप में दी की गई सूचना के लिए सूचना देने वाले आपूर्तिकर्ता से यह अपेक्षा है कि वे दी गई सूचना के साथ अच्छे कारण का विवरण दें कि वह सूचना क्यों प्रकट नहीं की जा सकता और/अथवा इस सूचना का सारांश संभव क्यों नहीं है।

27. अगोपनीय रूपांतर को गोपनीय सूचना के साथ अधिमानतः उस सूचना के आधार पर सूचीबद्ध अथवा ब्लैंक आउट/सारांश का प्रदर्श होना अपेक्षित है जिसके आधार पर गोपनीयता का दावा किया गया है। अगोपनीय सारांश गोपनीय आधार पर दी गई सूचना के सार की उपयुक्त समझ देने के लिए पर्याप्त ब्यौरे में होने चाहिए। तथापि, अपवाद स्वरूप परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकार यह दर्शा सकते हैं कि यह सूचना सारांश के लिए संवेदनशील नहीं है; सारांश क्यों संभव नहीं है, इसका एक विवरण प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुरूप दिया जाना चाहिए।

28. प्राधिकारी प्रस्तुत सूचना की प्रकृति की जांच पर गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार अथवा रद्द कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी संतुष्ट हैं कि गोपनीयता के लिए अनुरोध आवश्यक नहीं हैं अथवा सूचना देने वाला सूचना को सार्वजनिक करने के लिए या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसे प्रकट करने के लिए प्राधिकृत करने हेतु अनिच्छुक हैं तो वे उस सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

29. किसी सार्थक अगोपनीय रूपांतर के बिना अथवा गोपनीयता के दावे के संबंध में अच्छे कारण के विवरण के बिना किया गया कोई अनुरोध प्राधिकारी द्वारा रिकार्ड में नहीं लिया जा सकता है। प्राधिकारी संतुष्ट होने पर तथा दी गई सूचना की गोपनीयता की आवश्यकता स्वीकार करने पर उस सूचना को प्रदान करने वाले पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसे प्रकट नहीं करेंगे।

**३. सार्वजनिक फाइल की निरीक्षण**

30. नियम 6(7) के अनुसार, कोई भी हितबद्ध पक्षकार अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतर से युक्त सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है।

**४. असहयोग**

31. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार सूचना देने से इंकार करता है और अन्यथा उपयुक्त अवधि के भीतर आवश्यक सूचना प्रदान नहीं करता अथवा जांच में काफी बाधा डालता है, तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और उनके पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम रिकार्ड कर सकते हैं तथा केंद्र सरकार को आवश्यक समझी जाने वाली सिफारिश कर सकते हैं।

सुनील कुमार, अपर सचिव एवं महानिदेशक

### MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

#### INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 28th March, 2019

(Case No. O.I. 03/2019)

**Subject:** Initiation of Anti-Dumping investigation concerning imports of “Chlorinated Polyvinyl Chloride (CPVC)- Whether or not further processed into compound” from Korea RP and China PR

1. **F. No. 06 /03 /2019-DGTR.**—M/s. DCW Limited and M/s Kem One Chemplast Pvt. Ltd. (hereinafter referred to as “petitioners” or “the applicants”) have filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority) in accordance with the Customs Tariff Act 1975, as amended from time to time (hereinafter referred to as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter referred to as the Rules), for initiation of anti-dumping investigation concerning imports of Chlorinated Polyvinyl

Chloride (hereinafter referred to as the subject goods or product under consideration), originating in or exported from China PR and Korea RP (hereinafter referred to as the subject countries).

**A. Product under Consideration**

2. The product under consideration in the present investigation is “Chlorinated Polyvinyl Chloride resin (CPVC) - whether or not further processed into compound”. CPVC resin is processed with ingredients like stabilizers, lubricants, impact modifiers, processing aids, pigments to form the CPVC compound. CPVC is available in two grades - (a) Pipe grade and (b) Fitting grade.
3. CPVC is a thermoplastic produced by chlorination of Polyvinyl Chloride resin. It is significantly more flexible and can withstand higher temperatures than standard PVC. CPVC has excellent corrosion resistance at elevated temperatures. CPVC is ideally suited for self-supporting constructions where temperatures up to 200 °F (90 °C) are present. CPVC is significantly ductile, allowing greater flexure and crush resistance. Additionally, the mechanical strength of CPVC makes it a viable candidate to replace many types of metal pipe in conditions where metal's susceptibility to corrosion limits its use. It is typically very difficult to ignite and tends to self-extinguish when not in a directly applied flame.
4. The product under consideration is classified under chapter 39 of Customs Tariff Act, 1975 and the subheading 39049000. However, the product has also been imported under these subheadings- 39042110, 39042190, 39042210, 39042290 and 39049000. The custom classification is indicative only and not binding on the scope of the investigation.

**B. Like Article**

5. The applicant has claimed that though the subject goods can be produced through two processes; (dry process and wet process), there is no difference in the product on account of different technology being used. The applicant has further claimed that product under consideration produced by the domestic industry is comparable in terms of physical & chemical characteristics, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification with the subject goods imported from the subject countries.
6. The applicant has also claimed that the subject goods produced by the domestic industry is technically and commercially substitutable with those goods imported from the subject countries and, hence, should be treated as ‘like article’ under the Rules. Therefore, for the purpose of the present investigation, the Authority treats the subject goods produced by the domestic industry in India as ‘Like Article’ to the product under consideration being imported from the subject countries.

**C. Domestic Industry and Standing**

7. The petition has been filed by the M/s DCW Limited. M/s Kem One Chemplast Pvt. Ltd. has also separately petitioned seeking imposition of anti-dumping duty. M/s DCW has claimed that it is the sole producer of the subject goods in India at present and a new entrant in the market. M/s Kem One Chemplast Pvt. Ltd. has claimed that it intends to set up manufacturing facilities for production of the product and had to put on hold its investment in view of adverse market due to dumping of the product in the Country. As per available records, the applicant company viz. M/s DCW is the sole domestic producer and eligible to constitute domestic industry within the meaning of Rules 2(b) and satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5(3) of the Rules supra. M/s Kem One Chemplast Private Limited is also considered as Indian producer of subject goods albeit at project stage and will be investigated during the course of investigation.
8. There are some companies in India, who do not produce CPVC resin, but import CPVC resin, process the same into compound, largely for captive consumption for making pipes. However, there is also a company who is importing resin from its affiliated supplier, processing the same into compound and selling in the market. The petitioner has also stated that there may be some importers of the resin from China or Korea who may be selling the compound in the market, in addition to their own captive consumption. The companies who do not have manufacturing facilities for production of CPVC resin and are merely compounders processing imported resin into compound, have not been considered as “domestic producer” of the product for the purpose of proposed investigations in accordance with Rule 2(b).

#### **D. Subject Countries**

9. The present investigation is in respect of alleged dumping of the product under consideration from China PR and Korea RP.

#### **E. Normal Value**

10. The petitioner has claimed that China PR should be treated as a non-market economy and the normal value should be determined in terms of Annexure I, Rule 7 of the Rules. The petitioner has claimed normal value in China on the basis of import prices into India from third countries namely; Japan, Thailand and USA, as the petitioner could not get relevant information on price or constructed value in market economy third country. However, the Authority has *prima-facie* considered the normal value of subject goods in subject countries on the basis of constructed values computed in terms of Para 7 of Annexure I to the Rules.

11. The petitioner has claimed normal value for Korea RP on the basis of prices at which the domestic consumers in Korea are buying the material for domestic consumption from international suppliers. The petitioner has claimed that such consumption price in Korea RP is a comparable price in the ordinary course of trade paid for the like article and is therefore satisfies the “consumption price” test determined under Section 9A1(C). The Authority has *prima-facie* considered the normal value of subject goods in subject countries on the basis of constructed values as made available by the applicants for the purpose of this initiation

#### **F. Export Price**

12. The export price has been estimated by the petitioner on the basis of DGCI&S import data and after making adjustments towards ocean freight, marine insurance, commission, bank charges, port expenses and handling charges etc. During the course of investigation, the Authority will also analyse transaction-wise import data from Directorate General of Commercial Intelligence & Statistics (DGCI&S)

#### **G. Dumping Margin**

13. The normal value and the export price have been compared at ex-factory level, which shows significant dumping margin from the subject countries. There is sufficient *prima facie* evidence that the normal values of the subject goods in the subject countries are significantly higher than the ex-factory export price, indicating, *prima facie*, that the subject goods are being dumped into the Indian market by the exporters from the subject countries.

14. There is sufficient *prima facie* evidence of the significant dumping margins to justify initiation of antidumping investigation.

#### **H. Injury and Casual Link**

15. Information furnished by the applicant has been considered for assessment of injury to the domestic industry. The applicant has furnished evidences regarding the injury having taken place as a result of the alleged dumping in the form of increased volume of dumped imports in absolute terms and in relation to production and consumption, price suppression, price underselling, significant financial losses, negative ROCE, negative growth in various parameters, etc.

16. The applicant has also claimed that dumping of the product under consideration is materially retarding the establishment of the domestic industry. The production, sales, capacity utilization and market share of the domestic industry is quite low considering the demand for the product in the Country and considering that the domestic industry commenced commercial production sometime back.

17. From the foregoing, the Authority *prima facie* finds sufficient evidence of dumping of the subject goods originating in or exported from the subject countries, injury to the domestic industry and causal link between the alleged dumping and injury exist to justify initiation of an anti-dumping investigation in terms of Rule 5 of the Rules, to determine the existence, degree and effect of alleged dumping and to recommend the amount of antidumping duty, which if levied, would be adequate to establish as well as removal of the ‘injury’ to the domestic industry.

**I. Initiation of anti-dumping investigation**

18. The Designated Authority, in view of the foregoing paragraphs, initiates antidumping investigations into the existence, degree and effect of alleged dumping of the subject goods originating in or exported from the subject countries.

**J. Period of Investigation**

19. The period of investigation for the purpose of the present investigation is 1<sup>st</sup> April 2017 to 30th September 2018 (18 months). The injury investigation period will, however, cover the periods 2014-15, 2015-16, 2016-17 and the POI. The period of investigation has been divided into quarters for the purpose of injury analysis in view of shorter length of data of domestic industry. The data beyond the POI may also be examined for the purpose of analyzing performance of domestic industry.

**K. Time Limit**

20. Any information relating to the present investigation should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 days) from the date of publication of this Notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the AD Rules.

21. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses and offer their comments to the domestic industry's application within forty days (40 days) from the date of publication of this Notification. The information must be submitted in hard copies as well as soft copies.

**L. Submission of information**

22. The known exporters in the subject countries, the Government of the subject countries through their embassy in India, the importers and users in India known to be concerned with the product are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Authority at the following address:

**The Director General,**  
**Directorate General of Trade Remedies,**  
**Ministry of Commerce & Industry,**  
**Department of Commerce,**  
**4th Floor, Jeevan Tara Building,**  
**5, Parliament Street, New Delhi -110001.**

23. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner (downloadable from the website of the Authority at [www.dgtr.gov.in](http://www.dgtr.gov.in) within the time limit set out above. Any party making any confidential submission before the Authority is required to submit a non-confidential version of the same to be made available to the other parties.

**M. Submission of Information on Non-Confidential basis**

24. In case confidentiality is claimed on any part of the questionnaire's response/submissions, the same must be submitted in two separate sets (a) marked as Confidential (with title, index, number of pages, etc.) and (b) other set marked as Non-Confidential (with title, index, number of pages, etc.). All the information supplied must be clearly marked as either "confidential" or "non-confidential" at the top of each page. The interested parties are required to follow guidelines contained in Trade Notice No. 10/2018 dated 7th September, 2018 of this Directorate.

25. Information supplied without any confidential marking shall be treated as non-confidential and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect any such non-confidential information. Two (2) copies of the confidential version and of the non-confidential version must be submitted by all the interested parties.

26. For information claimed as confidential; the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such Information cannot be disclosed and/or why summarization of such information is not possible.
27. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out /summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, parties submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summarization; a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.
28. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.
29. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim may not be taken on record by the Authority. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided; shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

**N. Inspection of Public File**

30. In terms of rule 6(7) any interested party may inspect the public file containing non-confidential versions of the evidence submitted by other interested parties.

**O. Non-Cooperation**

31. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

SUNIL KUMAR, Addl. Secy. & Director General